bureaucrats or a task-force of bureaucrats. Again bureaucrats come into the picture. Now comes service tax on slaughter houses for large animals. They will come in the net. Who will decide it? A bureaucrat will decide it. There may be a bureaucrat soon who will decide that goat is small animal and cow is a large animal. Therefore, there will be no service tax on the first and on the latter if it is killed. Then the exemption of service tax. This is what is going to happen.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Does the Congress Party think that goat is a large animal?

SHRI V.N. GADGIL: The question is not what the Congress Party thinks. I am predicting what your bureaucrats are going to do. One can see the bureaucratic hands throughout the Budget. What is the rationale for some of the taxes? I don't understand. What is the rationale for levy on tractors and food processing industries? Why is there reduction of duty on perfume unless you are of the view that more perfumes will be used because the Budget smells! That is the only rationale I can tell you. This is a weakness of BJP which you have adopted. Though you are not 100% BJP, you have adopted it. You always have literative views.

चाल, चेहरा, चरित्र, भूख, भय, भ्रष्टाचार
सरल, सम्मान और समाधान

Now you have Saral, Samman and Samadhan. It is going to go the same way. What happended to *bhookh, bhaya* and *bhrashtachar* or to *chal, chehra* and *charitru* is going to happen to you. Now you have quoted Rabindranath Tagore and said that you intend to cross the sea. I want to give you a friendly warning. The sea is stormy and turbulent and you have not provided for any lifeboats. I feel that the whole Budget will sink like the Titanic and soon you will have to bring another Budget. That is what is going to happen. I have great respect for your integrity. I don't doubt your honesty or your integrity. But I have some doubts about your judgements. That is why I mentioned all these things. I am sorry to say that history will record it not as Yashwant Budget but as *Nashwant* Budget. It will go into history

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Message from the Lok Sabha, Secretary-General.

## MESSAGE FROM THE LOK SABHA

**The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1998**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to report the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1998, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 9th June, 1998.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Vice-Chairman, will the Government come out with a statement about the possible storm in Gujarat? Or have we got to read it in the newspaper tomorrow?

THE VICE-CHAMRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now we are on the General Budget. Naresh Yadav.

## THE BUDGET (GENERAL), 1998-99 (Contd.)

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन गांव से आता हूं इसलिए अपनी समझ से जो बात इस बजट में मैंने देखी और समझी है वित्त मंत्री जी का ध्यान उस पर आकृष्ट करना चाहूंगा।

सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जल कृषि के लिए महत्वपूर्ण साधन है। जल के सहारे हम जमीन की सिंचाई करते हैं जिससे कि देश का उत्पादन बढ़ता है। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री

जी से कहना चाहता हूं कि सिंचाई की योजना बिहार में सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई कोसी कैनाल योजना। कोसी कैनाल योजना बीरपुर बैराज से प्रारंभ होकर उस समय के पूर्णिया जिले, कटिहार जिले के अंत तक आती है। उस योजना ने बजाए जमीन को उपजाऊ बनाने के, उसकी उर्वर शक्ति बढ़ाने के पूरे उत्तर बिहार की जमीन को सिल्टेशन अर्थात बालू से भर दिया जिससे कि बजाए उत्पादन के उत्पादन में ह्रास हो गया है। इसलिए हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसका असेसमेंट किया जाए, देखा जाए कि क्या खामी है, क्या कमी है, कहां इस योजना में फर्स्ट फाइव इयर योजना में कमजोरी रही जिससे इस सिंचाई की योजना से बजाए किसानों को लाभ मिलने के हानि ही मिल रही है।

हम इसके साथ साथ माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी कहना चाहेंगे कि बिहार के मुंगेर में डकरानाला और गंगा के किनारे बक्सर से लेकर साहबगंज तक हम लिफ्ट इरीगेशन को कर सकते हैं और केन्द्र सरकार के पास जो योजनाएं लम्बित हैं जैसे डकरानाले की योजना, सुल्तानगंज की पाइप लाइन, कहलगांव की पाइपलाइन, यहां हम लिफ्ट करके गंगा के पानी को फेंक सकते हैं। गंगा के पानी में सिल्टेशन कम है बजाए कोसी के पानी के। जो कोसी कैनाल योजना है उससे यह ज्यादा फायदेमंद हो सकता है लेकिन आज तक अधर में लटकी हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि इन पर ध्यान दिया जाए।

माननीय वित्त मंत्री जी, आपने बंजर भूमि विकास पर अपने बजट भाषण में जोर दिया है। आप भी अच्छी तरह से इस बात से अवगत हैं। बंजर भूमि विकास में आपने अपना बजट बढ़ाया है। बहुत स्वागत योग्य है। 1600 किलोमीटर में गंगा बहती है और इस 1600 किलोमीटर में बिहार में जब गंगा प्रवेश करती है बक्सर के पास में तो आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि बक्सर के पास से गंगा दोनों ओर कटाव शुरू कर देती है और कटाव करने के कारण वह सारी की सारी जमीन दियारा कहलाती है। इसलिए वित्त मंत्री महोदय, बंजर भूमि विकास के साथ साथ आप दियारा भूमि विकास को भी इस बजट में जोड़ लें तो बड़ी कृपा होगी। हिंदुस्तान के किसानों के लिए बहुत बड़ी भलाई होगी। दियारा में पानी की कमी नहीं है, वहां तो बंजर जमीन नहीं है। पानी ही पानी है, बगल से नदी बह रही है। अब हमारे बिहार में दियारा है, कहीं कोई नाम होगा, किसी प्रदेश में कोई अन्य नाम होगा। पूरे देश की नदियों के बगल में जो जमीन है, किनारे वाली जो जमीन है जो कटाव वाली है उसको हम उपजाऊ बना सकते हैं। पानी देकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि देश की आमदनी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ सकता है।

महोदय, आपने ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्व-रोजगार योजना को बढ़ावा देने की बात की है। हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि आज हर आदमी, हिंदुस्तान का हर नागरिक स्व-रोजगार करना चाहता है। और चूंकि मैं बिहार प्रदेश से आता हूं इसलिए बिहार की बात को अच्छी तरह से आपके सामने रखूंगा। हमारे इलाके में एक कालीन उद्योग प्रमुख है। बड़े-बड़े व्यापारी लोग इलाहाबाद में बैठते हैं और बिहार का मजदूर यहां से सामान ले जा करके, कच्चा माल ले जा करके कालीन बनाता है। अगर इसके लिए सभी सुविधाएं वहां के मजदूरों को मुहैया कर दें तो बड़ी संख्या में उन्हें रोज़गार मिल सकता है। एक कालीन की कीमत कम से कम 25 हजार रुपये होती है, लेकिन उसकी मजदूरी उस बेचारे गरीब आदमी को हजार या दो हजार रुपये के बीच में ही मिलती है। स्वरोज़गार में यह बहुत बड़ा काम हो सकता है जिससे कि वहां का गरीब बेरोज़गार आदमी इस रोज़गार को कर सके।

महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने किसानों के ऋणों की समस्या के बारे में बताया है, तो हम बताना चाहते हैं कि किसान आखिर ऋणी क्यों हो जाता है, बैंक से लोन ले करके बैंक को अदा क्यों नहीं कर पाता है। अभी की किसान की जो हालत है वह मैं आपको बताता हूं। बिहार में आज की डेट में पंजाब से भी ज्यादा मकई पैदा हो रही है और उस मकई की लागत अर्थात् उसे पैदा करने में 400 रुपया प्रति क्विंटल खर्चा आता है और आज किसान उसे 340 रुपये प्रति क्विंटल बेचने के लिए बाध्य है। जब लागत से कम कीमत पर किसान बेचेगा तो किसान की क्या दशा होगी? वह उसे कहां भेज रहा है, वह कलकत्ता को भेज रहा है, वह पंजाब को भेज रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि वह भेज तो स्टार्च फैक्टरी में रहा है इसलिए जब यह फैक्टरी उत्पादित वस्तु की जगह पर नहीं लगेगी तब तक उस वस्तु का उपयोग कैसे होगा? किसान को ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी और उसको लागत हम कैसे देंगे? इसलिए हमारा आग्रह यह है कि बिहार जिन दो चीज़ों में बहुत आगे बढ़ा है बनोला और मेज़ प्रोडक्शन में तो इसके लिए कोई बड़ा वहां पर फूड प्रोसैसिंग प्लांट हो या स्टार्च फैक्टरी हो। इससे किसानों का बहुत बड़ा काम हो जाएगा और रोज़गार भी मिलेगा। महोदय, इसके साथ-साथ आपने पिछले साल देखा होगा कि पूरा आलू

बर्बाद हो गया। रुपया, आठ आना किलो, कोई पूछने वाला नहीं था। आप अपने बजट में प्रावधान कीजिए कि पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज व्यापक पैमाने पर बनाए जाएं जिससे कि हम लोग वहां फल को और आलू को रख सकें, और स्टोर कर सकें, ताकि सही समय पर जब उसकी लागत किसान को अच्छी आए तो वह बाजार में बेच सके और किसान को उसका लाभ मिल सके।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमें जोनल डिवेलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि किसी क्षेत्र में मकई हो रही है, किसी क्षेत्र में कपास हो रही है, किसी क्षेत्र में धान हो रहा है, तो इस तरह से आज यह इंबैलेंस है। योजनाएं अलग-अलग जोनलवाइज़ बांटना पड़ेंगी। इस देश में विभिन्नता में एकता है। आप देखेंगे पंजाब में गेहूं और बासमती चावल बहुत अधिक पैदा हो रहा है तो बिहार आज मकई अधिक पैदा कर रहा है, बंगाल धान अधिक पैदा कर रहा है, उसी तरह से महाराष्ट्र कपास पैदा कर रहा है, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। इसलिए जोनलवाइज़ बांट करके उसकी डिवेलपमेंट का प्लानिंग करना ठीक है कि कैसे हम इस जोन को यह चीज़ मुहैया करें और आप वहां किसानों को सस्ते दाम पर मुहैया करें जिससे कि सही-सही विकास हो सके। इस बार उत्पादन का आपका जो 200 मिलियन टन का लक्ष्य है वह उत्पादन इस बार खाद्यान्न का पूरा नहीं करने जा रहे हैं। हम उत्पादन इस तरह पूरा कर सकते हैं कि हम सारा किसानों को मुहैया करें। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान हम इस ओर आकृष्ट करेंगे निश्चित तौर से आपने जो कहा है बजट में कि यूरिया का इतना उपयोग हो रहा था जमीन में, क्योंकि हम लोग, यूरिया सस्ता मिलता था, और जमीन में बजाय डी०ए०पी० डालने के, पोटाश डालने के, यूरिया ही डाल देते थे। सोचते थे कि यूरिया डाल दिया गेहूं बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। तो जमीन का स्वास्थ्य निश्चत तौर से बिगड़ रहा था। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? यूरिया का दाम पहले एक और अब पचास पैसे बढ़ा दिया। तो पहले पचास रुपया बोरी, अब पचीस रुपया बोरी बढ़ाया है। हम आग्रह करेंगे अगर किसानों का सच्चा भला चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री महोदय, तो आपने जितना यूरिया का दाम बढ़ाया है, उसी अनुपात में आप पोटाश का और फास्फेट का जो जरूरी है, जो आप अपने वक्तव्य में बोलते हैं एन०पी०के०, तो आपको पोटाश का, फास्फेट का दाम घटाना पड़ेगा। जो बहुत ऊंचा है। इसलिए आप ऐसा तालमेल कर दीजिए जिससे कि किसानों को एहसास हो कि हमें ज्यादा "पे" नहीं करना पड़ा और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रह जाय। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश की जमीन की उर्वरा शक्ति भी बरकरार नहीं रहेगी और हम आप को निश्चित तौर पर कहेंगे कि एन०पी०के० बारे में आप ने बार-बार कहा है तो आप ने जो नाइट्रोजन का दाम बढ़ाया है, उस के साथ आप को फॉस्फेट और पोटाश का दाम घटाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो आप ने 50 पैसे किलो बढ़ा दिया है, हालांकि इस बारे में आप का आश्वासन भी अखबारों में आया है, आप अपने उत्तर में हमें जरूर बताएं और आप या तो इसे वापिस ले लीजिए नहीं तो उस के दाम को बैलेंस कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष जी, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इंदिरा आवास के लिए आप ने 20 लाख अतिरिक्त दिया है, लेकिन वित्त मंत्री जी आप को भी आश्चर्य लगेगा कि आज एक आवास बनाने में—छत की ढलाई, प्लास्टर वगैरा के सारे काम में एक सौ बोरी सीमेंट लगता है, अब उस में 5-10 बोरी कम हो सकता है। फिर आज की डेट में 100 बोरी का दाम 18 हजार रुपए है। तो आज 18 हजार रुपया गरीब आदमी को, जिसे आप आवास दे रहे हैं सिर्फ सीमेंट का पे करना पड़ रहा है। फिर पता नहीं क्यों जैसे ही आप की सरकार आई है, वैसे ही सीमेंट का दाम 130 रुपए से बढ़कर 175 रुपए हो गया है। यह मैं बिहार के अपने जिले की बात कर रहा हूं। अब इस में 4 रुपया ढुलाई का जोड़ लें तो वह 180 रुपए के हिसाब में अपने घर लाने में पड़ता है। तो सीमेंट अचानक 130 रुपए से 170—175 रुपए तक बढ़ गया। यह पता नहीं कैसे बढ़ गया? लोहे का दाम जो 1550 रुपए था आज 1750 रुपए हो गया है। गिट्टी के दाम, बालू के दाम अचानक बढ़ गए हैं। इन सब चीजों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज तक जितने इंदिरा आवास बने हैं, उन के पूर्ण होने का कितना परसेंटेज है? मेरे ख्याल से तो उस के पूरा होने का परसेंटेज बहुत कम होगा। वह गरीब अच्छी हालत में तो पहली किस्त उठा लेता है और फिर जब वह बनता नहीं है तो आगे उसे प्रशासकीय लोग पैसा नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि उतना बना लो, प्लिंथ लेवल तक बना लो फिर दूसरी किस्त देंगे लेकिन उस गरीब का प्लिंथ लेवल तक भी नहीं बन पाता। इसलिए जो आप की 20 हजार की सीमा है, उसे बढ़ाया जाए ताकि गरीबों के घर बन सकें।

उपसभाध्यक्ष जी, इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप ने मुझे बोलने का समय दिया, आप का बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डा० महेश चन्द्र शर्मा** (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बजट एक संक्रमणकालीन बजट है। हमारे विपक्ष के वक्ता जिस नए भारत की बात पर व्यंग कर रहे हैं। महोदय व्यंग साहित्य की अच्छी प्रवृत्ति है, लेकिन किसी भी संक्रमण दौर को समझने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। संक्रमण का दौर जब ध्यान से देखा-परखा जाता है तो भविष्य की दिशा स्पष्ट होती है। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के पास कोई जादू नहीं था कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पर विदेशियत की ओर सरपट दौड़ती अर्थ-व्यवस्था को वह ऐसा कोई "यू" टर्न देते कि वह स्वदेशी हो जाती। महोदय, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की गति मंथर होती है। ऐसे में वित्त मंत्री जी ने एक साहसिक प्रयत्न किया है जिसके लिए मैं उन का अभिनंदन करता हूं। यह पहली बार हुआ है कि बजट ने कृषि और ग्रामीण विकास को एक विशिष्ट वरीयता प्रदान की है। यदि भारत को विश्व मंच या अर्थव्यवस्था का वैशिष्ट कायम करना है तो हमें अपनी कृषि और ग्रामों को प्राथमिकता देनी होगी। बम्बई के सेनैक्स से जो अर्थव्यवस्था को नापते हैं, निश्चित ही वह इस बजट से निराश हुए होंगे। मैं चाहता हूं कि वह निराश हों।

मान्यवर, इस बजट की आजकल विशेषकर अंग्रेजी अखबारों में बड़ी आलोचना हो रही है। मुझे लगता है कि यह आलोचना ही इस बजट की सबसे बड़ी प्रशंसा है। जब शुरू-शुरू में यह बजट आया था तो पता नहीं क्यों उन लोगों ने इस बजट की बड़ाई कर दी थी, परन्तु ज्यों-ज्यों पढ़ने के बाद उनको लगा कि गलती हो गई तो इस तरह का अखबारों में आने लगा। आज ही एसोचेम के जो अध्यक्ष हैं एन० लक्ष्मण,, उन्होंने कहा है—"The Budget lacks vision and strategy". बजट के पास न दृष्टि है, न रणनीति है। दृष्टि कौन सी नहीं है और रणनीति कौन सी नहीं है? यदि वित्त मंत्री जी कुछ ऐसे काम कर देते, जिन कामों की बड़ी पूछ है आज की ग्लोबलाइजेशन इकोनोमी में, तो यह लोग वित मंत्री जी बड़ी भूरि-भूरि प्रशंसा करते। यदि वित्त मंत्री जी ऐसा कुछ कर देते, बाई बैक आफ शेयर की व्यवस्था कर देते तो यह कहते कि वाह-वाह, इकोनोमी में गति आ गई। यदि वित्त मंत्री जी, हमारे यहां जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ रिजर्व है, उनको डीरिजर्व कर देते तो यह कहते कि वाह-वाह, बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा लिया गया है। यदि वित्त मंत्री जी पूर्व वित्त मंत्रियों का अनुसरण करते हुए कस्टम ड्यूटी घटा देते तो कहते कि ग्लोबलाइजेशन की ओर यह बड़ा भारी कदम है। यदि वित्त मंत्री जी ने कैपिटल एकाउण्ट आफ कन्वरटेबिलिटी की व्यवस्था कर दी होती तो यह लोग और खुश होते। पिछली बार चिदम्बरम जी ने तो विधेयक ला ही दिया था बीमा क्षेत्र को यदि वित्तमंत्री जी विदेशियों के हाथों खोल देते तो उनके लिए यह बजट ग्लोबलाइजेशन की इकोनोमी में एकदम फिट होता और यह वित्तमंत्री जी कहलाते कि यह कोई रूढ़िवादी जनसंघ या बीजेपी के आदमी नहीं हैं बल्कि यह तो बड़ी ही प्रगतिशील, उदारवादी और मनमोहनोमिक्स के नए अवतार हैं। लेकिन, वित्त मंत्री जी, आपने यह नहीं किया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने उनको निराश किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशियों के हाथों गिरवी रखना चाहते थे। आपने सबक लिया इंडोनेशिया से, आपने सबक लिया मलेशिया से, आपने सबक लिया दक्षिण कोरिया से और आपने ऐसा नहीं किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आपको जो विरासत चिदम्बरम जी ने दी थी, मनमोहन सिंह जी ने दी थी, उस विरासत के आप वारिस नहीं बने, उसके आप उत्तराधिकारी नहीं बने, यह अच्छी बात है।

मान्यवर, मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था आजादी के बाद पहले दिन से एक समस्या है और वह समस्या यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था पर मनमाने साइन बोर्ड टांगते रहे हैं। जब हम आजाद हुए तो हमारे मन में महात्मा जी के प्रति आदर था और हम गांधीवादी अर्थव्यवस्था को साकार करने में लग गए थे, परन्तु पता नहीं क्या हुआ, अचानक यह अहसास हुआ कि नहीं, नहीं हमें गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बजाय सामजवादी अर्थव्यवस्था लानी चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद हमको लगा, मनमोहन सिंह जी आ गए, कि नहीं, नहीं, अभी तक जो अर्थव्यवस्था हम बनाए हुए थे वह समाजवादी थी, अनुदारवादी थी इसलिए अब हमको उदारवादी हो जाना चाहिए। तो हमारी अर्थव्यवस्था गांधीवादी, समाजवादी थी या उदारवादी थी, हमने अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में मौलिक चिंतन से सदा नकारा और उसकी का परिणाम है कि हम विदेशी पैमानों से अपनी अर्थव्यवस्था को नापते हैं।

मान्यवर, डा० मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस के लोगों ने इस बात की बड़ी शिकायत की है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध आने वाले हैं और वित्त मंत्री जी को होश ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता यदि इस देश

में कोई तो कहता कि वह देश कौन होता है प्रतिबंध लगाने वाला। अमरीका में जो प्रतिबंध का कानून बना है, यह कानून अपने आप में साम्राज्यवादी कानून है, इस कानून की भर्त्सना होनी चाहिए। इस कानून को लेकर के अमरीका को दुनिया में एक्सपोज़ किया जाना चाहिए लेकिन हम अपने ही देश को डराना चाहते हैं, डरा रहे हैं कि प्रतिबंध आएंगे तो क्या होगा। क्या प्रतिबंध पहले नहीं आए हम पर, जब क्रियोजॉनिक इंजन हमको रूस देने वाला था और अमरीका ने उस पर दबाव डाला था कि भारत को क्रियोजॉनिक इंजन न दिया जाए? क्या यह प्रतिबंध नहीं था? यह कानून का प्रतिबंध नहीं होगा, पर यह दादागिरी का प्रतिबंध था और यह प्रतिबंध हमारे लिए नितांत शुभकारी साबित हुआ। अमरीका ने हमको क्रियोजॉनिक इंजन नहीं लेने दिया, हमारे वैज्ञानिकों ने 8 साल में क्रियोजॉनिक इंजन बना लिया। अमरीका ने हमको सुपर कम्प्यूटर नहीं दिया, हमने सुपर कम्प्यूटर बना लिया। दुर्भाग्य यह है, मान्यवर, कि हम अपनी प्रतिभा को केवल तब जगाते हैं जब कोई विदेशी हमको इसके लिए ललकारता है। यदि सुपर कम्प्यूटर अमरीका हमको दे देता तो हम न बनाते, क्रियोजॉनिक इंजन रूस दे देता तो हम न बनाते और इसलिए पहले तो मनमोहन सिंह जी साउथ-साउथ कोआपरेशन के महामंत्री थे, पता नहीं साऊथ-साऊथ करते-करते कैसे ग्लोबलाइजेशन में पहुंच गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको अर्थव्यवस्था नापने के साम्राज्यवादी मुहावरों से अपने आपको मुक्त करना चाहिए। जब तक हम अर्थव्यवस्था को इन मुहावरों से नापते रहेंगे, तब तक हम सदा धोखे में रहेंगे। मान्यवर, आपसे उधर के लोग पूछ रहे हैं कि आपने इतना कम बढ़ाया है, इससे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? मान्यवर, समाजवाद के दिनों का हमारा भगवान विदेशी कर्ज था और उदारवाद के दिनों का हमारा भगवान हो गया विदेशी निवेश। या तो हम विदेशी कर्ज पर अवलम्बित रहेंगे या विदेशी निवेश पर अवलम्बित रहेंगे, हम स्वदेशी की बात नही करेंगे, स्वावलम्बन की बात नहीं करेंगे और यह जो विदेशी कर्ज की पिशाज-पूजा है, उसका यह परिणाम है कि आज जितना आपका रिवेन्यू रिसीट है, लगभग उतना ही आपको विदेशी कर्ज का ब्याज का मूल चुकाना है। अपने पूरे रिसीट को यदि आप चुका देंगे तो देश के लिए बजट क्या बनाएंगे? शून्य में से बजट क्या बनाएंगे? मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाता, आरोप नहीं लगाता लेकिन यह आत्मालोचन का मुद्दा है कि 50 साल में हमारा देश दिवालियेपन के कगार पर क्यों पहुंचा? क्यों हमारा देश इस प्रकार के ऋण-जाल में फंसा हुआ है? हमें इस ऋण-जाल से देश को निकालने के लिए सांझे प्रयत्न करने चाहिए और दलबंदी के आरोपों से यदि हम मुक्त रहें तो अच्छा रहेगा।

मान्यवर, हमने स्वीकार ही कर लिया कि जो अपने को विकसित कहते हैं, वे विकसित हैं और किसी ने हमको अविकसित कहा तो हमने मान लिया कि हम अविकसित हैं। महोदय, यह बहुत पीड़ा की बात है जब कोई विद्यार्थी अपने स्कूल या कालेज में सुनता है कि अविकसित हैं तो क्या उसमें कोई स्वाभिमान पैदा होगा और जिनको आप विकसित कहते हैं, उनके प्रति यदि उसकी ललक पैदा होगी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि विकसित देशों की होड़ में जाने की हमारी इच्छा, यह आत्मघाती इच्छा है। क्या हमको नहीं मालूम कि आज अमरीका दुनिया का सबसे विकसित देश कहलाता है। लेकिन वह ही दुनियां का सबसे बड़ा प्रदूषक देश भी है। प्रकृति का प्रदूषण उसी ने किया है। ओज़ॉन लेयर उसने छेदी है। इतना कार्बन-डाइआक्साइड छोड़ता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा हो गया है उत्तरी ध्रुव पिघलेगा तो क्या होगा—जल प्रलय होगी और इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आज दुनियां के विकसित देश कहलाते हैं वह दुनियां के प्रकृति के प्रदूषण करने वाले सबसे बड़े देश है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आज विकसित देश कहलाते हैं वह सामाजिक रूप से तनावों से घिरे हुए देश हैं और इसलिए मुझे इसमें कोई रूचि नहीं है कि कोई हमारी तुलना उन पशिचमी देशों के करे और और हमें कोई यह कहे कि हमको वैसा विकास करना है जैसा उन्होंने किया है। मुझे लगता है मान्यवर, अर्थव्यवस्था में कुछ चीज जोड़नी चाहिए। जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था है वह जी०डी०पी० की बात तो करता है, ग्रौस डॉमेस्टिक प्रोडक्शन हैं लेकिन इसका कहीं आभास नहीं देता कि जी०डी०पी० प्राप्त करने के लिए क्या खर्च किया, किसी कीमत पर जी०डी०पी० प्राप्त की गई है। इसका कोई गणित यह कोई पश्चिम का अर्थशास्त्र नहीं करता और इसलिए आज जरूरत हो गई है कि ग्रौस डॉमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ-साथ इसका भी आंकड़ा दिया जाए कि यह प्राप्त करने के लिए ग्रौस डेस्ट्रक्शन आफ नेच्युरल रिसोर्स कितना हुआ है, आपने कितना पानी कंज्यूम कर दिया, कितना कोयला कंज्यूम कर दिया, कितने वनों को काट लिया, कितनी भूमि बंजर कर दी। जब कि इस प्रोपर्टी रिसोर्सेज के डेस्ट्रक्शन का आंकड़ा नहीं मिले तो जी०डी०पी० का आंकड़ा झूठा और साथ ही केवल जो पैसे का आंकड़ा है उस पैसे के आंकड़े में मानव का सुख नहीं होता और इसलिए इसकी भी जरूरत है कि

अर्थव्यवस्था का आंकलन करते समय एक मूल आंकड़ा बनाया जाए और वह आंकड़ा है ग्रौस हैप्पीनैस आफ पीपुल। इस अर्थव्यवस्था ने मनुष्यों को कुल मिलाकर के कितना संतुष्ट किया, कितना सुखी किया। जब तक अर्थव्यवस्था के इन मूलभूत सिद्धांतों पर हम पुनर्विचार नहीं करेंगे और यह जो पाश्चात्य मुहावरा है इस पाश्चात्य मुहावरे में ही अपने आपको भटकाते रहेंगे तो मैं समझता हूं मान्यवर, हम जिस दुश्चक्र में फंसे हैं उसमें फंसे रहेंगे उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं बधाई देता हूं कि वर्तमान वित्त मंत्री जी ने इस दुश्चक्र को तोड़ने का प्रयत्न किया है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि बंजर भूमि को विकसित करने के लिए आपने सोचा। मान्यवर, देश में बड़ी बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? केवल सड़कें, कम्युनिकेशन, इलैक्ट्रीसिटी? इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश की भूमि है, जल, जमीन, जंगल, जानवर यह इस देश का नेच्युरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले 50 साल में हमने अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। जरुरत इस बात की है कि जब हम अपने देश के ढांचे के बारे में विचार करें तो हम सोचें कि पिछले 50 साल में हमने अपनी कितनी अनउर्वरक भूमि को उर्वरक किया। हमने अपनी भूमि की संरचना से कितने लोगों को जोड़ा। जो देश में जल है, मान्यवर, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान में जल का अभाव हमेशा रहा है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जल को संग्रहित करने की वैज्ञानिक विधियों का विकास किया था। पिछले 50 साल में वह समाप्त हो गई और पानी का जिस प्रकार पाश्चात्य देशों को देख-देखकर हम दुरूपयोग कर रहे हैं, अपने पानी में इंफ्रास्ट्रक्चर का हम नाश कर रहे हैं, कितनी नदियां है हमारे पास, जो काम हमारी रेलें करती हैं, जो काम हमारी सड़कें करती हैं वह काम बहुत सस्ते में यह नदियां भी कर सकती हैं। लेकिन रेलों के लिए, निहित स्वार्थों का दबाव रहता है। इतने सस्ते में यातायात व्यवस्था को जाएगी तो उनको यह अच्छा नहीं लगेगा और यह तो एक शुरूआत है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी जब अगला बजट पेश करेंगे तो यह जो पूरा भारतवर्ष का धन है, सम्पदा है, जल है, जमीन है, जंगल है, जानवर है, उसके आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम, एक नयी दिशा वह जरुर देंगे। महोदय, हमारी अर्थव्यस्था में होने जो अपने साइन बोर्ड बदले हैं, उसका बड़ा नुकसान हुआ हैं। आजकल हमारे यहां मार्किट में कहते हैं कि बड़ी मंदी आयी हुई है। यह मन्दी क्यों आयी हुई है? पिछले पचास सालों में समाजवाद के नाम पर हमारे देश की उद्यमशीलता को, ऐंटरप्रेन्योरशिप को राहू लग गया है क्योंकि केवल सरकारी उत्पादन ही नहीं, निजी उत्पादनों में भी 80-90 प्रतिशत शेयर का खरीददार केवल सरकार रही है। अब यदि सरकार खरीददारी न करे तो भारत का उद्योग दौहायमान हो जाता है, डरने लगता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने देश की उद्यमशीलता का आवहन करें, देश में जो ऐंटरप्रेन्योरशिप है, उसका आवहन करें और उसका आवाहन मंत्री जी ने किया है। मान्यवर, यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का सरकारीकरण कर दें और न ही यह कोई अच्छी बात कि हम पूरी अर्थव्यस्था को निहित स्वार्थों के हाथ में झोंक दें। न तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को निहित स्वार्थों में झोंक सकते है और न केवल सरकार के हाथों में। इसलिए, महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने एक मंत्र दिया है कि "अर्थव्यवस्था को व्यष्टि और समष्टि की एकरूपता के अनुकूल होना चाहिए।" बजट और अर्थव्यस्था को न व्यक्तिवादी होना चाहिए, न समाजवादी होना चाहिए वरन् व्यष्टि और समष्टि की एकरूपता के अनुकूल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमें प्रयास करना होगा और इस दिशा में प्रयाण की यह पहली शुरूआत है। आपने यूरिया का दाम बढ़ाया, यह एक अभिनंदनीय कार्य था। लेकिन जैसी स्थितियां हैं, मेरे दल सहित सभी एमपीज़ इस बात से खफा है कि किसान नाराज हो जाएगा। लेकिन यूरिया का उपयोग कम होना ही चाहिए। जैविक खादों का उपयोग बढ़ना ही चाहिए। जैविक खादों के उपयोग को, जैविक खादों के उत्पादों को प्रोत्साहित करना अच्छा काम है, अभिनंदनीय काम है और रासायनिक खादों को हम जितना कम करें, उतना अच्छा है। लेकिन जब शराब की लत पड़ जाती है तो यह जानते हुए भी शराब बुरी चीज है, शराब नहीं छूटती है। मान्यवर, यह यूरिया भी धरती की शराब है। लत पड़ गयी है, छूटती नहीं है। छुड़ाने के लिए कुछ प्रयत्न करना होगा। लोगों का कहना मानकर आपने कुछ राशि कम कर दी है लेकिन कुछ ऐसा करना होगा जिसके, जैविक खादों का उपयोग हमारे खेतों में बढ़े। इसके लिए मेरा सुझाव है, यदि वह संभव हो तो वह करना चाहिए कि हमें जैविक खाद इस्तेमाल करने वाले किसानों को एक प्रमाण पत्र देना चाहिए। वह भूमि के रक्षक हैं और उस प्रमाण पत्र के आधार पर उनको कुछ अतिरिक्त प्रकार की ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो किसान जैविक खादों का उपयोग करेगा, उसको सरकार उस प्रमाण पत्र के आधार पर कुछ अतिरिक्त ऋण सुविधाएं देगी तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने से हमारी भूमि की रक्षा होगी और भूमि को पचास साल में जो नशाखोर बना दिया है, हम उसको नशे से मुक्त कर सकेंगे। महोदय, उत्पादन शुल्क का मुद्दा काफी विवाद का मुद्दा रहा है। अब जो

पिछली सरकारों की नीति रही है, उसका परिणाम यह हुआ है कि उपभोक्ता बाजार में भी बड़ी-बड़ी एम० एन० सीज़ आ गयी हैं और बड़ी-बड़ी कम्पनियां भी आ गयी हैं क्योंकि लघु उद्योगों से हमने बहुत सी चीजें डीरिजर्व कर दी हैं। अब ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां उत्पादन करती हैं, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगाती हैं और ये उत्पादन शुल्क भी न दें तो यह कैसे हो सकता है? इन सब पर उत्पादन शुल्क लगना ही चाहिए। यह आपका निर्णय उचित है। लेकिन इसमें एक मुद्दा विचारणीय है और वह मुद्दा यह है कि उत्पादन शुल्क के लिए आपने 50 लाख टर्न ओवर की सीमा रखी है। मान्यवर, जैसा महंगाई का जमाना है उसमें वर्ष भर में 50 लाख टर्न ओवर हो गया, 4 लाख महीने का टर्न ओवर हो गया। 4 लाख का टर्न ओवर तो छोटी सी दुकान का भी होता है। इसलिए आज सब लोग परेशान हैं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। बीकानेर से मेरे पास फोन आए। वहां का पापड़ उद्योग, वहां का भुजया उद्योग, वहां के लोग इस उत्पाद शुल्क से आतंकित हैं और उन्होंने अपना उत्पादन बन्द कर दिया है। बीकानेर से जहां टनों माल रोज बाहर जाता था, वहां के लोग चुप हो कर के बैठे हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि हम वित्त मंत्री जी से निवेदन करेंगे तो वे जरूर इस पर विचार करेंगे। यह जो खाद्य सामग्रियां हैं, कोई भी उनको पैक करके, कोई नाम देकर के बेचता है, इस मात्र से वह ब्रांड हो जाता है और 50 लाख का टर्न ओवर बहुत ही कम होता है। वित्त मंत्री जी यदि यह संभव हो तो आप इस टर्न ओवर को कम से कम तीन करोड़ कर दीजिए। लघु उद्योगों की सीमा में उनको ला कर तीन करोड़ के टर्न ओवर को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दीजिए और इसके ऊपर जो लोग हैं उनसे उत्पाद शुल्क अवश्य लीजिए और उनसे लिया ही जाना चाहिए।

कल डॉ० अशोक मित्र बोल रहे थे। मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना। मैं समझता हूं कि वह अपनी आलोचना में कनसिस्टेंट हैं और उन्होंने कहना भी चाहा कि जो कंवरटिड है उसको क्या कंवरटिड करेंगे? जिस मात्रा में स्वदेशी का हमारी अर्थ-व्यवस्था में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उस मात्रा में वह नहीं हो पाया है और वह नहीं हो सकता था। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार की आलोचनाओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जो पिछली सरकार, विगत सरकार थी वह सरकार आज सत्ता में नहीं आई। वह सत्ता में नहीं आएगी इसकी घोषणा पिछली बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने की थी। उन्होंने संत तिरुवल्लवर की एक कविता अपने भाषण में पढ़ी थी। मैंने वह तमिल में लिखी है। मेरा उच्चारण तमिल का तो हो नहीं सकता पर मैं बोलने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कविता पढ़ी थी, "इसका अर्थ है कि जो राजा अपने आलोचकों की परवाह नहीं करता वह शत्रुओं के बिना ही नष्ट हो जाता है।" चिदम्बरम जी ने हमारी आलोचनाओं की परवाह नहीं की। वह अपने ड्रीम बजट के नशे में कुछ ऐसे रहे कि वापस लौटकर न आ सके।

महोदय, प्राप्त परिस्थिति में यह बजट जो बना है यह बजट अपनी सब सीमाओं के साथ एक अभिनन्दनीय बजट है, एक अच्छा बजट है और हमारे वित्त मंत्री जी की जो आलोचनाएं की गई हैं वह उनकी अवश्य परवाह करेंगे।

हमारे देश की एक और बड़ी समस्या है और वह समस्या यह है कि एक तंत्र बना हुआ है जिसको ब्यूरोक्रेसी वगैरह कहते हैं। उसका भी एक माइंड सैट है, उसका भी एक दिमाग बना हुआ है तो वित्त मंत्री जी आपने तो पूर्ण परिवर्तन की बात नहीं की है लेकिन आज के अखबार में एक खबर है, वह खबर मैं पढ़ता हूं। यह खबर नवभारत टाइम्स में है। इसमें लिखा है, "भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी कंपनियों की भारतीय शाखाओं को अपना मुनाफा स्वदेश भेजने की अनुमति दे दी है। ये शाखाएं प्राधिकृत डीलरों द्वारा ही यह काम कर सकेंगी। इससे पहले रिजर्व बैंक ने भारत में सक्रिय विदेशी बैंकों को भी यह अनुमति दी थी कि वे अपने अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश भेज सकते हैं और इसके लिए रिजर्व बैंक को पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई रुपये की चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया है।"

मान्यवर, आपके बजट में तो यह कदम नहीं है और बैंक स्कैम जब हुआ था 1992 में, जोकि भयानक स्कैण्डल था। उसके बाद इस मुनाफा भेजने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया था। यह अपने आप ही कैसे खुल गई आपके बजट भाषण से इतर होकर। मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर थोड़ा अंकुश लगे तो अच्छा है। एक और खबर है अखबार में। आपने तो बजट में साफ कहा था कि आप बीमा क्षेत्र को खोल रहे हैं केवल भारतीय उद्योगों के लिए। लेकिन यह अखबार की खबर है—

No decision yet on foreign entry into Insurance.

आपके इतना कहने के बाद भी यह डिसिजन अभी तक कैसे नहीं हुआ? मंटोक सिंए अहलुवालिया के संदर्भ से यह बात कही गई है तो मुझे लगता है कि जैसे

पॉलिसी के मुद्दे पर हुआ, छोटी-मोटी और बातों के मुद्दों पर भी होता है। इसलिए तंत्र का जो माइन्ड सैट है, उस माइन्ड सैट के साथ नए भारत की दिशा कैसे कदम बढ़ा सकेगी? इसके लिए बहुत से सुघड़ प्रशासनिक कदम हमें उठाने होंगे। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी अवश्य करेंगे। उपसभाध्यक्ष, महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI JIBON ROY (West Bengal): I look at the Budget from the workers' point of view and from the point of view of the common masses. I have a belief, a serious belief, Sir, that politically there may be differences between BJP and other political parties, but at least so far as economics is concerned, you demarcate yourself from your predecessors. Even in my support base I have seen that BJP can do anything in the other front so far as economics is concerned, they will now let the workers and the common people down. Sir, the people have been totally belied. The workers, poor agriculture workers, the common people are totally belied. They are practically let down. My leaders, Dr. Ashok Mitra, while speaking here, said," Your Budget is a carbon copy of your predecessor's Budget." I will go further. If your Budget figures— along with the declaration that you have made in your Speech—are taken together they are much more reprehensible, inhuman and also degenerative of the reform programmes and they go totally against the people. The Statement you have made is concerning disinvestment. As far as the Congress Party or your predecessors are concerned, they never said, at least in the declaration, that public sector will be liquidated. They have never said that. They have said sick public sector units will be wiped out; they have said viable public sector units will be revived; they have said that disinvestment will be made up to the level of 51 per cent. And in one declartion you have said so. You thought that Parliament is supreme. Outside nobody is there, people are not there, people are not supreme. You have said that the sick industries would be disposed of, they will be closed. And workers will be given a golden kick.

Secondly, you have said that all the assets of the Indian Airlines, ports will be handed over to private hands, because we are going to reduce it to 49 per cent within two years' time. Do you think that the people will accept it? Do you believe it from heart? Will people ever accept it? You have said that in other sectors, irrespective of whether the industries make profit or loss, their disinvestment will go up to 74 per cent. Neigher the Congress nor the previous Govenment could dare to say, you mean to say, that the Board of Directors in the Steel Authority of India would be replaced with private people and Indian people will accept it? It is most reprehensible. It is a distortion of the reforms. It is a degeneration of the reforms.

You have announced that the Urban Land Ceiling Law would be repealed; the ceiling on urban land would be removed. It means, you are thinking of establishing a promoter raj, in place of the licence raj. The promoters would be given money. They would be given loans and all the suburb land areas would be handed over to these people mostly traders who, incidentally, form your main support-base. Nobody would accept the position. You should bear this in mind.

Insurance businss would be thrown open to the private sector. This is what you have proposed. You want to give the provident fund money to the private businessmen. Do you think the workers are going to accept this? You feel very proud that you have conducted the nuclear tests. You are not only militarising. You are also regimenting State and a section of the people. On the other hand, you are favouring the traders and the big business houses. If you have the might, you try to do it. I don't mind. But I warn you. There would be resistance. There would be resistance in the streets. Please bear this in mind.

You have made a statement that the non-performing assets which constitute about ten per cent would be handed to a private group. They would manage it,

who are responsible for the creation of this problem. These are the people who have siphoned off money. The Committee would consist of them! There would not be any Parliamentary Committee.

Therefore, Sir, taking both the things together—the statements made by the Government and the Budget—I would say that the policies are anti-people.

Mr. Vice-Chairman, Sir, a great change is taking place in the policy direction of the Budget and the economy. Till the Sixth Five-Year Plan, the policy direction of the Budget was equality, bridging the gap between the incomes of different sections of the society and, self-reliance. These were the three pillers of the policy direction of the Government, as reflected in the Budget, till the Sixth Five-Year Plan. In the Seventh Five-Year Plan, when Dr. Manmohan Singh was the Deputy Chairman of the Planning Commission, he replaced the word 'equality' with 'equity'. 'Equality' has been replaced by 'equity and social justice'. Of course, 'self-reliance 'remained. But, from the Eighth Five-Year Plan, 'equity' gone; 'social justice' gone. 'Globalisation' came.

At the same time, there was a new dimension—the distributive side of the economy was given good bye. So long, as students of economics, we have been taught that an economy has two sides, namely, the growth side and the distributive side. But, from the Eighth Five-Year Plan onwards, the distributive side has gone. The poor are being left to the mercy of the big people. For the Government, in economic terms, only the twenty per cent of the population, which they are targeting, matters. They think that if money is poured on this twenty per cent of the population, the other people would automatically get it. But, Sir, it does not happen, in real terms.

I do not know what is the direction of your economy. I do not know what is the direction of your budget. You claim that you are an alternative to the preceding Governments. All right; if you are not an alternative to the Congress Party, you say it; you announce it. Your claim that you are an alternative to the Congress Party, to the preceding Governments; has been proved to be false. At least, you have taken off your mask.

Sir, where was the BJP earlier? They were on this side. They were like *chupa rustam*.. They were opposed to disinvestment. They were opposed to privatisation. Even in their Election Manifesto, it was not there. But one fine morning, there is a change in the stand. The people would not accept it. The socalled Swadeshi direction you are giving concerns only the twenty per cent; not the entire population of the country.

Sir, when the private sector economic regime was introduced in our country, we were told that the Government need not have to put money in industries. We were told that because of this, there would be higher allocations for poverty alleviation programmes, for health and for other welfare measures for the poorer sections of the people. We were told that this kind of a regime would result in more production and productivity. It was claimed that the wages of workers would increase. It was claimed that employment opportunities would increase. But what has happened to all these claims?

What has happened actually, Sir? I had no time to go through the figures. If you go through the figures of the Seventh Plan, when Dr. Singh was the Deputy Chairman of the Planning Commission, whatever achievement was there in budgetary terms, the same percentage is continuing. If you take the total allocation and the spending in respect of these Leads to which people are concerned, they are almost the same percentage. The percentage did not increase. But we have lost our public sector. We have lost our sweat and blood. We have lost the hold on the economy of the poor people, people are drawn below poverty line in every passing days. Will you please return to all these things which have already gone?

As Mr. Ashok Mitra has said if you compare the two Budgets, the Budget placed by Mr. Chidambaram and your Budget, they are almost equal. The percentage of the Plan outlay to the total Budget in his Budget was 26 per cent and that in yours is 26.8 per cent. The percentage of the capital investment to Plan in his Budget was 40 per cent, and that in yours is 39 per cent. The total capital expenditure to the total budgetary allocation in his Budget was 21 per cent, and that in yours is 22 per cent. There is no difference. So far as the economic platform is concerned, you are all equal. You take the basic, main heads through which money goes to the poor people. Take the food subsidy and the expenditure on civil supplies. They spend 3.1 per cent of the Budget. Your allocation is 3.3 per cent. On health, their allocation was 0.62 per cent, and yours is 0.65 per cent. On family welfare, their's was 0.78 per cent. Yours is 0.90 per cent. You are the champions of the small-scale industry. On this, their's was 0.43 per cent. Yours is 0.38 per cent. Labour whom I represent, are the most oppressed. They are not represented. They are being kicked out by your proposal. Your proposal is: "Please take the golden kick, surrender the public sector, sacrifice the public sector and go out." For these poor labour, theirs was 0.26 per cent. Yours is 0.21 per cent. Therefore, Sir, it is almost the same because you belong to the same class as they represent you hold the same position and you represent the same class. Don't say that you are an alternative to them.

You have talked about the public sector sick industry. All right, I agree with you. Since you have decided about it, I understand, it has gone. You have said that the profit-making industry would be disposed of up to 74 per cent. It has gone. What about those industries which are in the BIFR? If the revival packages are given, what will be their fate? How much have you given to heavy industry? Theirs was Rs. 120 crores. You have given only Rs. 140 crores. Sickeness is more in heavy industries. Already, the revival package of Rs. 60 crores has been sanctioned by previous Govts. How would you give the money? Please tell this to us. That is why I say that labour is not in the agenda. Neither was it there in their Budget nor is it here in your Budget. On Non-Plan, theirs was Rs. 257 crores, and yours is Rs. 215 crores.

SHRI YASHWANT SINHA: You must be aware of the fact that whenever the BIFR decides a case, it is always on the basis of assistance from banks. It is never on the basis of grants from the Government.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): The Government of India which is the promoter, has to give 30 per cent of the revival scheme. You are talking of banks. I am talking about what he has said.

The scheme has already been sanctioned by the BIFR and the Ministry of Industry. The Government of India's allocation is Rs. 2.5 crores. The United Bank of India which is the operating agency and which is supposed to give the money for the working capital, has refused to give any money for that till now. The revival scheme is being unrevived. Unless the promoter, the Government of India, gives 30 per cent equity, no scheme can take off. At least 20, 30 companies are very much on the revival scheme. They are only waiting for the nod from the promoter. Unless the promoter gives that, it cannot be helped.

SHRI JIBON ROY: Sir, your statement has vindicated my point that the Government is not with the workers. It is independent. Workers will have to deal with their management locally. That is the position that you have stated, if I have understood on clearly.

Sir, I would like to know what the Government is going to do with the unpaid statutory dues to the workers. No provision has been made. The amount has shoot-up Rs. 480 crores. Provident Fund and Gratuity fund has been taken

away and diverted to the production process by many public sector management, because no Budgetary support was there from the Government. Now, workers are on the street and the Government does not feel concerned. No provision for this has been made in the Minister's statement. Therefore, I say workers know their fate has to be decided by the workers themselves, but the Government should agree that the Government is no more for the workers, is no more for the agricultural workers, is no more for the poor.

Sir, we know these are certain key promoters which regulate production process in manufacturing and mining. Dr. Ashok Mitra had explained about it. I have the figure of such a yardstick. Electricity is a yardstick to judge overall production scenario. Previously steel was taken as a yardstick for industrial growth. If you take the entire figure from 1980 to 1988-89, the total growth of electricity production was 100 per cent, but the growth in output was only 55 per cent during 1990-91 and 1997-98. I am alarmed for other reasons also. Out of the electricity production, the percentage use of electricity in industry between 1980-81 and 1985-86 was 67.6 per cent, while between 1990-91 and 1995-96 its use was 45 per cent. That means electricity is not required for industrial growth. While it is being claimed that growth rate is multiplying, use of electricity is not increasing. It in strange that entire economy is being converted into a screw-driver economy; economy is being converted into an assembling economy. Our industry is not producing. It is importing goods and assembling them. This gets reflected in the growth rate, which is disastrous to the country's economy.

SHRI YASHWANT SINHA: Just a moment, please. Facts must be clarified. I do not have to defend it, because we were not in Government then. You know who turned it into a screw-driver economy. But, I must tell you that an equal proportion of electricity today is being used by the agriculture sector.

SHRI JIBON ROY: If you look at the percentage growth, it is regressive in character.

SHRI YASHWANT SINHA: Forty per cent is going to agriculture.

SHRI JIBON ROY: That means in industry it is going down. I am talking about industry. Industrial production is not taking place. An assembling economy is coming up. Growth rate in Agriculture is also minimal I would now like to draw your attention to the poor people, who do not have a chance to represent here. We are sure that unemployment will grow. I have taken the figures from the Economic Survey of India and from the circulars of the Employment Exchanges. In 1981, total employment in the organised industries, both in public and private sector, was 228.29 lakhs. In 1990, it was 263.74 lakhs — a growth of 34.45 lakhs. In 1991, it was 267.34 lakhs. In December, 1995, it was 279.31 lakhs.

Between 1981—1990 Public and Private together, there was a growth of only 34 lakhs while between 1991 and 1996 growth is 9.34 lakhs only. You should note this dangerous thing. The Government should take a note of the fact that between December 1995 and December 1996 the employment in Government sector has gone down by four lakhs. The employment in the Government sector is being replaced by the employment in the private sector. Again permanent worker, contract labourers, daily wage workers are being employed. That means the employment is going down. The quality of employment is also going down. The daily wage workers segments constituted of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes. The prevailing minimum wage is also declining. In Maharashtra it is between Rs. 80.35 and Rs. 9.25. We talk of liberalisation. We talk of economic growth. The mimimum wage in the most industries lived state like Maharashtra is Rs. 9.50. The highest wage in Maharashtra is Rs. 80.35 and the minimum is Rs. 9.25. The highest wage in Kerala it is between Rs. 76.40 and Rs. 19.50. In

Tamil Nadu, in the minimum level, highest is Rs. 56.25 and the minimum is Rs. 10. These are the ranges of wages given to the labourers. You are following the same economic line which create poverty line. That is why I would like to advise for whatever political line you may take, don't alienate yourself from the poor people, common people and workers.

Therefore, the entire trade union is opposed to our budget. I understand the problem of the BMS who have supported your Government during the elections. Along with them I had visited many industrial cities. Everywhere they have said that if the BJP comes to power there would be no privatisation or disinvestment. After the placement of Budget one of the leaders told me, "Please give me some poison. Let me take it." All the national trade union organisation is Bengal gave a call for *bandh* on the 3rd July. You can understand the reaction of the common masses. I urge upon the Finance Minister ro revise the budget in favour of poor.

I would like to said please do not kill the public sector. When you kill the public sector, you are killing its technicians, engineers and workers. The Government has built Public Sector over some years together. If you fight for the cause of workers, we are with you. If there is a reasonable understanding with the trade unions, we are ready to resolve it and settle it. Let there be a talk between the Government and the leaders of the trade unions.

Sir, the previous Government had constituted the Disinvestment Commission. They have made some recommendations. In the terms of reference they have mentioned that the Disinvestment Commission can give any recommendation, but it would be discussed with the leaders of the trade unions. But at no point of time or at no place was this matter discussed with the leaders of the trade unions. I came to know through some reliable sources that a talk is going on to give a statutory status to the Disinvestment Commission. Then, everything will go. The Parliament will have no right to discuss it. Since a long time I am in the trade union movement. I do politics a little bit. After, working for 35 years in a factory, I understand workers' problem and their nerve. If you perpetuate these politics, I caution you, there will be a disaster in the trade union front, in the working class front. After all, workers still play important role in framing public opinion.

No doubt, you have given some concession to the employees of the Central Government. But calculations reveal after an employee attains the age of 56 years in the Gvoernment Department, he will get wages from his own money. An extension of two years from 58 years to 60 years do not help them much out of their provident fund money and gratuity money, whatever interest comes, is sufficient for their wage. Under your liberalisation policy, you have made no law for the agricultural workers. You have allocated Rs. 0.26 lakh to the labour ministry. I am associated with the Labour Department. With that money, they cannot manage hundreds of posts in industrial tribunals remained vacant. Magistrates are not posted for years together in different states. But those vacancies cannot be filled because there is no money. They cannot regulate privatising minimum wages in different states because of the financial constraint. Since the labour is termed as third class, therefore, the same is the condition of Labour Ministry. You have to accept that position. I request you to consider that point. I might have used some hard words. But I believe that the Finance Minister will not mind that. He will appreciate my emotions and feelings. My words are not the main thing. The main thing is the content of my speech. Kindly take that content into account. With these words, I conclude my speech. Thank you.

THE FINANCE MINISTER (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, the hon. Member has made a very energetic

speech. He must be hungry. I have an announcement to make. Light refreshment is being served in the Central Hall refreshment counter. Please go and partake.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, this is the time for dinner and they are giving snacks. (*Interruptions*) The requirement of the people is different and the B.J.P. is giving something else.

SHRI YASHWANT SINHA: We believe in light charge, light refreshment.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Is this also *Swadeshi*?

**The Vice-Chairman (Shri Triloki Nath Chaturvedi),** *In the Chair*

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL (Gujarat): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Budget. Sir, I would like to bring to you notice that neither I am an economist nor a student of Economics. But as a lay person, I would like to put some points and would like to express the feelings of a common man. The Budget introduced by the BJP Government is, as the "Indian Express" puts it, a pedestrian Budget. While Mr. J. Mulraj, in the "Times of India", describes it as not even pedestrian Budget. Whatever it is, it is a directionless Budget, no doubt. The reasons are obvious. It has created an impression that the Budget is negotiable and with a little pressure, you can get it changed. The hon. Finance Minister announced an increase of one rupee in the price of urea fertilizer. It has given rise to an uproar in Parliament by the Opposition parties. The farmers also have reacted strongly. Instead of trying to convince about the logic of the need behind the rise in urea price, the Finance Minister, the very next day, withdrew fifty per cent of the increase. With a continued pressure from the Opposition, there will be a decrease of another 25 per cent, and now the BJP Government is inclined to totally withdraw the price rise in urea. Did the Finance Minister and the Prime Minister not think about the impact of price rise in fertilizer and its cumulative effect on agriculture and farmers at the other end? Were they not serious about it? Are the demands in Budget a child's play or a fun? Whatever their thinking may be, it has certainly made a fun of the BJP Government. This is not only one point that has adversely affected the image of the BJP Government. The *faux pas* with petroleum price rise, the Finance Minister announced one rupee price rise for one litre of petrol, with increase in excise duty. Instructions were issued to implement the rise on the same day. And instead of one rupee rise, the prices were hiked to Rs. 4.35, to Rs. 5/- at the petrol pumps, and within a few hours, crores of rupees were collected. It aroused a great anger among the customers, and with the Opposition raising the issue, the price-hike was corrected. But what about the extra amount paid by the customers and collected by the Government? The Opposition has demanded to refund the illegitimate collection, but the Government is not prepared to consider this legitimate demand of the customers. Never in a span of 50 years of our history such backtracks and horrible blunders have taken place. It has made a public spectre of the BJP Government. It is not a question of damaging the public image of the BJP before the masses. It has damaged the image of our nation in the international eyes.

The third point I would like to put before the House is that the present Budget has come before us at a time when the BJP Government had done five atomic explosions at Pokhran and Pakistan had retaliated with five to six explosions in turn. As a result, USA, France, the Scandinavian countries, Australia, Canada, Japan, and some other nations have declared economic sanctions on India. The UN and the World Bank have not declared sanctions, but the World Bank has suspended seven loan projects to begin with, and has continued to do so thereafter. The Finance Minister has consoled us by declaring that there will not be any adverse effects of the sanctions.

But in a public meeting at Bombay, our respected Finance Minister has accepted that the adverse effects will be observed after 12 to 18 months. I do not know whether or not our respected Finance Minister has information that there is already a price-hike in a variety of goods in the market. The stock market feels insecured. We observe a continuous declining trend in the share market, which is, in a way, a barometer of the economy of the nation.

Sir, I am sorry to say that the Finance Minister has miserably failed to reflect a total strategical plan to combat the economic fall-out due to the sanctions, revitalise the capital market, check inflation and create an atmosphere of confidence in the common man through the Budget. It has also failed to control the devaluation of the rupee and the cumulative effect. All these will lead to a financial crisis and a heavy price-rise. According to a known economist, at this rate, we will be galloping towards a double digit inflation which will hurt the poor most. The BJP Budget is hightly inflationary. The non-modvatable levy of 8 per cent on imports is described as to protect the domestic market. But it will also cost more the imports of raw material for small scale industries, and it will be difficult for them to make their ends meet. This will also create a crisis for small scale industries. I am worried that instead of encouraging "Swadeshi", it may have negative results and may adversely affect the employment opportunities. Even the Chairman of NALCO has commented that it will be difficult for them to take advantage of 8 per cent rise in levy because with constly raw material, the final products will be constlier and it will not be possible to stand competition in the market with higher prices.

Moreover, the items under the 8% excise include branded gheee, butter, cheese, tea-bags, milk powder, branded meat and fish, branded spices and many such items that are used by the common man. It will adversely affect the customers with limited income. I am worried, Sir, that the 8% excise on imports may not be as effective as the Finance Minister has thought of.

Again the Finance Minister laid stress on infrastructure development, say, water, power and roads. But I am sorry to point out that the amount alloted for watershed development programmes in the plan is Rs. 667 crores. It is a very small amount looking to the vastness of the need, whereas the addition is only Rs. 160 to last year's provision. After 50 years of independence we have only 36% irrigation facilities. It is not a question of water for agriculture alone. There are thousands and thousands of villages which have no source of drinking water or potable water. So, many of them use unhygienic water for drinking and become prey to diseases. He has provided a nominal increase of Rs. 325 crores, which will not be sufficient. Another critical issue is availability of power. Even in our national capital, New Delhi, we have power cuts, power breaks and low voltage problems. The position in remote villages will naturally be the worst. Nowadays, power is the most inevitable key to development and is a basic infrastructure facility for agriculture and industry as well. We are short of power as the demand is increasing day by day and the production is becoming less and less. There are so many hydel power projects which are in dispute. They are the sources of cheaper power which we need. The Narmada project, the Tehri dam project and many such other projects are in dispute. Will the Finance set up some authority with powers to resolve these disputes? Or, will he change the laws that help the anti-development activities of the activists? The transmission and distribution system also requires renovation. The SEBs are practically in a bankrupt situation. Privatisation has not helped due to the style of our political functioning. I would like to emphasize that promulagation of a Ordinance for establishing Central and State Electricity Regulatory Commission will prove to be only a face-saving

the easiest means of communication. May be, to cope with the deficits or for some other reason the Finance Minister has preferred to increase the rates of competition postcards from Rs. 2 to Rs. 3, inland letters from Re. 1 to Rs. 1.50, covers from Rs. 2 to Rs. 3 and parcels from Rs. 8 to Rs. 10 per 500 grams. This price hike will largely affect the poor, the rural masses, the common man. On the other hand, the provision of Rs. 3,320 crores, which is Rs. 500 crores more, for the National Highways Authority of India is too meagre and amount to cater to the needs of roads, national highways and bridges. Sir, roads are the basic infrastructural facilities. More funds should be allocated for roads. I would like to bring to the notice of the Finance Minister that the Ahmedabad-Bombay National Highway and so many other National Highways are starving of necessary finances for the last 10 years. There may be many roads and bridges which need the atention of the Finance Minister.

Sir, I would like to draw the attention of the Finance Minister towards certain particular issues which are of equal importance.

The textile industry is the prime industry of our country which is providing clothing to 95 crore people of our nation. Moreover, readymade garments, clothes and yarn have a capacity to capture a large international market and earn foreign exchange. But I am sorry to say that the textile industry is dying and there are hundreds of sick textile mills. Some mills have alrady been closed. BIFR was expected to revive the industry but unfortunately it has failed to deliver substantial goods. I don't want to go into the details of its causes. But, Sir, the difficulties of lakhs of unemployed labourers have not touched the heart of the Finance Minister. There is no provision to revive the textile industry. Will the Finance Minister declare some steps to strengthen BIFR and the textile industry?

In the same way, we talk much about health services to all by 2000. But no special provision has been made to extend the health services to small villages and the poor villagers or to upgrade the present facilities.

There are hospitals without doctors and doctors without medicines. The diseases like AIDS, cancer and frequent heart troubles have not been a cause of worry for the Finance Minister. On the contrary, some private hospitals and trusts used to provide yeoman services by extending health care treatment to patients. The Finance Minister felt that they were the sources of tax evasion and he has withdrawn 100 per cent exemption that was available to hospitals, medical research institutes and educational institutions. I would request the Finance Minister to reconsider this decision.

Education for all is also an equally important thing. I would like to congratulate the Finance Minister for providing free and compulsory education up to the fifth standard and for also providing free educaiton to women at all levels. But good intentions do not suffice. The plan allocation to educaiton has been substantially increased from Rs. 3,351 crores to Rs. 4,245 crores in the budget. But the Finance Minister has forgotten the fact that a large portion of the increase will be grabbed by higher education because the UGC has substantially increased the grades of the teaching and the non-teaching staff of higher education. This amount will be spent mainly on salaries and very little will be left for expansion and quality upgradation of primary educaiton.

Sir, so many vital issues have been side-tracked maybe due to the pressure of the bomb blasts or they have failed to attract the attention of the Finance Minister.

In the end, I would like to appreciate some of the measures taken by the Finance Minister, like incentives offered to telecommunication, provision of FEMA instead of FERA, though we

know very little about FEMA, tax holiday to housing projects, PLO card for NRIs and incentives to those who invest in the motherland.

"Kisan credit", increase in the income tax exemption limit to Rs. 50,000/-, increase in the taxes on vices like cigarettes etc., are the steps to be appreciated. But I would like to warn the Government that the picture is not so simple as the so called *Saral* Budget of the Respected Finance Minister. Only a provision of one form for new tax payers will not serve. Sir, I am worried that the "Samadhan" formula may open a new Pandora's box of corruption by the tax payers. May I ask the Government whether the simple and *Saral* looking provision is to satisfy the ever dissatisfied souls of some supporting partners of the BJP Government? With these words I conclude. Thank you.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister regarding irrigation because the present Government is giving much more importance as far as irrigation is concerned. So far as the Eighth Five Year Plan is concerned, the target that was fixed for irrigation was not achieved. So, I would like to know how a new project can be taken up with the old backlog. The second thing is, renovation and modernisation of irrigation projects have not been carried out properly. The amount is being provided to the State Government but the State Government is not spending for the projects for which it is intended to be spent. The other thing that I would like to know is, as far as strengthening of infrastructure relating to irrigation potential is concerned, the State Government are not serious and they are also not monitoring all the proejcts. So if agriculture has to be given priority, then the Government has to monitor the projects concerning innovation, modernisation and about irrigation facilities. The second thing is, Sir, in this Economic Survey of 1997-98, in the Postscript, it has been clearly mentioned, "Following the testing of nuclear devices by India in the second week of May 1998, one thing however, is clear: to the extent to which these reactions render external economic environment less friendly." So, we want to know the gravity of these sanctions. The third thing is, as far as social sector is concerned, the present Government is giving much more importance to social sector. Today, in the answer itself, the Finance Minister has stated that in "India: achievements and challenges in reducing poverty" published in May 1997 the World Bank has concluded that anti-poverty programmes have not been cost effective in reducing poverty. The third thing is when will huge amounts be spent in social sector? What will be cost effective in reducing poverty? The other thing I would like to know from the Minister is about Consolidated Fund of India. I want to know what is the percentage of the total expenditure charged on the Consolidated Fund of India. If there is an increase, what are the reasons thereof? The other thing that I would like to know is, what are the details of debt charges for which the Government of India is liable including interest and other expenditure relating to the raising of loans and in services and redemption of debt as provided in Article 112(3)? Further more, I want to know, what is the borrowing limit fixed by the Parliment as provided in Article 292? That last thing is that only 10 per cent of the rich are getting the benefit of economic reform. I would like you to elaborate on this.

Thank you.

**उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी):** श्री ओम प्रकाश कोहली। कोहली साहब आप 10 मिनट में खत्म कर देंगे जिससे कि दो-चार वक्ता और बोल सकेंगे?

**श्री ओम प्रकाश कोहली** (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी को जो अर्थ-व्यवस्था और आर्थिक स्थिति विरासत में प्राप्त हुई, वह जर्जर आर्थिक स्थिति है और 1997-98 का वर्ष चहुतरफा गिरावट का वर्ष रहा है। अर्थ-व्यवस्था मंदी की चपेट में रही है।

आर्थिक विकास की दर गिरकर 5 प्रतिशत रह गई है, कृषि विकास की दर में गिरावट आई है। कृषि उत्पादन 199 मिलियन टन से गिरकर 194 मिलियन टन रह गया है, औद्योगिक उत्पादन भी गिर गया है, निर्यात निष्पादन भी चिन्ताजनक रहा है, राजकोषीय घाटा 6.1 प्रतिशत को छू गया, पूंजी बाजार मंद और सुस्त हो गया, ऐसी आर्थिक स्थिति वित्त मंत्री जी को विरासत में प्राप्त हुई है इसमें से उन्होंने जिस बजट की रचना की है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उनका बजट एक सुस्पष्ट दिशा वाला बजट है। यह बजट बिगड़ी हुई और पटरी से उतरी हुई अर्थ-व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने वाला बजट है। यह व्यावहारिक बजट है, यथार्थवादी बजट है, प्रेगमैटिक बजट है। कहा गया है इस बजट की आलोचना करने वालों के द्वारा कि यह दिशाहीन बजट है यह ड्रीम बजट नहीं है, यह ठीक है, यह चटपटा बजट नहीं है, यह भी ठीक है। लेकिन जिस प्रकार की देश की जर्जर आर्थिक स्थिति वित्त मंत्री जी को विरासत में प्राप्त हुई है उसमें न ड्रीम बजट की जरूरत थी देश को और न चटपटे बजट की जरूरत थी। देश को एक सुसस्पष्ट दिशा वाले बजट की, एक प्रेगमैटिक बजट की ओर ऐसा बजट वित्त मंत्री जी ने देश को दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस बजट में बहुत सी सकारात्मक और स्वागतयोग्य विशेषताएं हैं। कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया है, उसे फोकस में रखा गया है। ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है ग्रामीण आवास को भी महत्व दिया गया है। बस्तियों को पीने के पानी की आपूर्ति कराने का प्रयत्न किया गया है। महिलाओं को निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है और शिक्षा के क्षेत्र में आबंटन में भारी वृद्धि की गई है। देश का आर्थिक विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर अवलम्बित है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बजट में बहुत जोर दिया गया है। यह बजट रोजगार का सृजन करने वाला है। इसमें इस प्रकार की योजनाएं हैं। जिनसे रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह बजट केन्द्रीय योजना राशि में वृद्धि करने वाला बजट है। केन्द्रीय सरकार का कुल खर्च रिवाइज्ड एस्टीमेट में 1997-98 के मुकाबले में 32,682 करोड़ रुपये अधिक होगा जिससे विकास को गति मिलेगी। प्लान एक्सपेंडीचर रिवाइज्ड एस्टीमेट के मुकाबले 11,372 करोड़ रुपया अधिक होगा जिससे निश्चित रूप से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बजटीय समर्थन फॉर सेन्ट्रल प्लान को भी 1997-98 के रिवाइज्ड एस्टीमेंट के मुकाबले 8,835 करोड़ रुपये अधिक है। इन सब चीजों का कुल समेकित परिणाम यह होगा कि इससे रूकी हुई अर्थ-व्यवयस्था को गति मिलेगी।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा है कि इस बजट में कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों को फोकस में रखा गया है। इसका उद्देश्य कृषि में गिरावट को समाप्त करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया गया है। हमारी कृषि योग्य जीमन का केवल 37 प्रतिशतहकी आश्वस्त सिंचाई के अंतर्गत है इसलिए सिंचाई पर जोर दिए जाने की जरूरत थी और यह कदम स्वागत योग्य है। कृषि क्षेत्र रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है इसलिए इस क्षेत्र पर किया गया खर्च रोजगार को बढ़ावा देता है हमारी अर्थव्यवस्था की नींव कृषि है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

किसानों के लिए क्रैडिट कार्ड की योजना स्वागत योग्य है इससे उनको ऋण के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कृषि क्षेत्र में योजनागत खर्च में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नाबार्ड के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है और महोदय, राष्ट्रीय कृषि नीति का दस्तावेज शीघ्र तैयार करके देश के सामने शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। सिंचाई के लिए जल-भंडारण और बंजरभूमि विकास जैसे कार्यक्रमों पर भी हमारे वित्त मंत्री जी ने ध्यान दिया है। ग्रामीण विकास और कृषि विकास दोनों जुड़े हुए क्षेत्र हैं। ग्रमीण ढांचागत विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की एक बुहत बड़ी कठिनाई जल की आपूर्ति की है। 1627 करोड़ की व्यवस्था जल आपूर्ति के लिए की गई है जिससे एक लाख हैबीटेशन लाभान्वित होंगे। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार आबंटन के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण की व्यवस्था को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है और इस बजट में ग्रमीण क्षेत्र के लिए ऋण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुआयामी प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने की योजनाएं हैं और नाबार्ड की शेयर पूंजी बढ़ाकर भी इस प्रकार की सहायता का उपाय किया गया है।

लघु उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार पैदा करता है लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए छोटे पैमाने के उद्यमियों का विकास करने के लिए इस बजट पर विशेष दृष्टि रखी गई है। लघु उद्योगों के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित हो सके, इसके लिए शाखा प्रबंधकों को

अधिकार दिए गए हैं। सिडबी की अधिक भूमिका होगी। अब, आईडीबीआई से सिडबी को डीलिंग किया गया है। कृषि और लघु उद्योग मिलाकर लगभग 80 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इस बजट में इन दोनों क्षेत्रों पर फोकस रखकर रोजगार की चुनौतीभरी समस्या पर भी आक्रमण बोलने का प्रयास वित्त मंत्री जी ने किया है। आठ प्रतिशत प्रतिकारी शुल्क लगाकर घरेलू उद्योग हेतु समान आधार तैयार करना, लेबल प्लेइंग फील्ड तैयार करना, यह स्वदेशी की भावना के अनुरूप है। इंस्पैक्टर राज को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बराबर जोर देती आई है। इंस्पैक्टर राज को हटाने के व्यवस्था भी की गई है। दो वर्षों के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्ति को दुगुना करने और अधिक मूल्य के विदेशी प्रस्तावों की स्वीकृति 90 दिन के अंदर करना, ये साहसपूर्ण कदम हैं जो वित्त मंत्री जी ने उठाये हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारी अर्थव्यवस्था का या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।

इस बजट में ऊर्जा, परिवहन और संचार के लिए योजनागत परिव्यय में 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। धनराशि इन क्षेत्रों के लिए पैंतालीस हजार दो सौ बावन करोड़ रुपये से बढ़ाकर 61 करोड़ एक हजार एक सौ छियालीस करोड़ की गई है।

सड़कें आर्थिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण आधार हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जो कि स्वागत योग्य है। आधार-भूत क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार की कर रियायतों का प्रावधान किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बढ़ाने की बात कही गयी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा किसी भी देश के विकास का बहुत बड़ा पहलू होता है। इस बजट में शिक्षा के लिए आवंटन की राशि बहुत बड़ी मात्रा में रखी गई है। लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि शिक्षा के लिए आवंटन में की गई है। लेकिन, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि यह बात सच है कि यह जो भारी आवंटन किया गया है इसका एक काफी बड़ा हिस्सा पांचवें वेतन आयोग के बाद जो शिक्षकों के वेतन-मान इम्प्रूव किए गए हैं, उस पर खर्च होगा। बहुत बड़ी संख्या में देश में निरक्षर हैं। इसको समाप्त करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण यह अभी कच्चा-पक्का चल रहा है। इसको मजबूत करने की जरूरत है। यह कड़ी निगरानी के अन्तर्गत भी ठीक प्रकार से जोर नहीं पकड़ पाया है। इस पर जोर दिए जाने की जरूरत है। लड़कियों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि मानव संसाधन विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र पर पैसे का प्रावधान करना उचित था और इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अब जरा वित्त बाजार की तरफ नजर डालें। कुछ नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं। बीमा क्षेत्र को घरेलू निजी कंपनियों के लिए खोला गया है। इसे विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोला गया है। दबाव के बावजूद नहीं खोला गया है। केवल घरेलू निजी कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र को खोलने से वित्तीय क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी और इससे लाभ होगा।

नान पर्फार्मिंग असेट की समस्या को सुलझाने के लिए असेट रीकन्स्ट्रक्शंस कंपनियों के गठन का कदम भी उपयोगी है, स्वागत योग्य है। देश को पूंजी की आवश्यकता है ही। अगर देश का आर्थिक विकास होना है तो आंतरिक पूंजी और विदेशी पूंजी दोनों की ही आवश्यकता है। वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया है। उन्होंने आनिवासी भारतीयों, एन०आर०आई० को पूंजी-निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया है, उन्हें आकर्षित किया है जब चीन अपने यहां की 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी समुद्र पारीय चीनियों से प्राप्त किर सकता है। तो भारत एन०आर०आई० को इस ओर क्यों नहीं प्रेरित कर सकता है कि वह बड़ी मात्रा में देश में पूंजी निवेश करें। यह दृष्टि से बजट में रखी गई है। इसके लिए पी०आई०ओ० कार्ड योजना इत्यादि कुछ योजनाएं भी रखी गई हैं। साथ ही विदेशी निवेशकों के निवेश प्रस्तावों पर 90 दिनों में निर्णय करना यह भी विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उचित कदम है। उपसभाध्यक्ष महोदय,....

**उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी):** अब समाप्त करिए।

**श्री ओम प्रकाश कोहली:** मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी):** कर डालिए, बढ़िए नहीं, समाप्त करिए।

**श्री ओम प्रकाश कोहली:** मैं पढ़ रहा हूं। मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं।

कर दरों में स्थायित्व का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। व्यक्तिगत अथवा कंपनी कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और कर आधार का विस्तार किया गया है। सेवा कर के दायरे को विस्तृत किया गया है और 12 नई सेवाओं को कर दायरे में लाया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आय कर की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दी जाए, यह मांग वेतन-भोगी लोगों द्वारा बराबर की जाती रही थी। लेकिन वित्त मंत्री जी ने 40 हजार से 50 हजार तक छूट की सीमा बढ़ाई है। अपेक्षा उनसे और अधिक थी।

समाधान, सरल और सम्मान इन तीनों स्कीमों पर हमारे कुछ मित्रों ने आलोचना करने, हंसी उड़ाने और रिडिक्यूल करने का प्रयास किया है। मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं उन्होंने पाजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना कर इन स्कीमों के पीछे की भावना का आदर किया? समाधान के माध्यम से करीब पौने सात लाख विवाद, जिन में 52 हजार करोड़ से अधिक की राशि फंसी हुई है, उस पर आक्रमण किया जा सकता है।

उसका समाधान ढूंढा जा सकता है और जो सरल योजना है, कर दाता को बहुत सीधे, सरल तरीके से एक पृष्ठ की विवरणी भरनी पड़ेगी। ईमानदार करदाताओं का सम्मान और प्रोत्साहन जो योजना है, यह भी स्वागतयोग्य योजना है। मैं अपनी बात को समेटते हुए कुछ चीज़ों को छोड़ रहा हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो 20 लाख अतिरिक्त मकान बनाने की बात इस बजट में की गई है, 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 7 लाख शहरी क्षेत्रों में, इससे रोज़गार के सृजन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, रक्षा बजट पर वृद्धि की गई है, 41200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग के लिए धन में भी 60 प्रतिशत तक जो वृद्धि की गई है, मैं समझता हूं कि देश की रक्षा संबंधी जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस प्रकार की परिस्थिति का आकलन रक्षा के संबंध में यह देश यथार्थवादी नज़रिये से करता है, उसको देखते हुए यह वृद्धि करना बहुत उचित था, उपयोगी था। कल्याण क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत अधिक आबंटन इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।

अंतिम बात कह कर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और वह यह है कि कुल मिला कर हमारे देश में अर्थ-व्यवस्था जिस स्थिति पर टिकी है उसमें जो टोटल राजस्व प्राप्तियां हैं, उनका 90-91 प्रतिशत इंटेरेस्ट पेमेंट पर, डिफेंस पर, सब्सिडीज पर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो जाता है। इसलिए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के जो दावे है, उनके लिए राशि बहुत कम रह जाती है। 1997-98 में कुल राजस्व प्राप्ति 1,38,514 करोड़ थी जिसमें इंटेरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडीज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें पुलिस, पेंशन और अदर जनरल सर्विसेज़ आती हैं, इन पर कुल मिला कर 1,29,169 करोड़ खर्च हुआ अर्थात् 93.2 प्रतिशत और 1998-99 के बजट में 90.4 प्रतिशत इस पर खर्च हो जाएगा। इस तरह से अर्थ-व्यवस्था के जो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनके तकाज़ों की पूर्ति में कठिनाई आती है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं केवल इतना निवेदन कर के कि क्या वित्त मंत्री जी इन दो तीन बातों पर और लचीले नज़रिये से विचार कर सकते हैं, यदि गुंजाइश हो तो करने की कृपा करें। तीन बातों का उल्लेख करता हूं बल्कि दो का उल्लेख करता हूं। एक बात आपके कहने से छोड़ देता हूं। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग उद्योग को अधिक राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिये। इस पर पुनःविचार करनी की कृपा करें। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं पर और अधिक प्रावधान की जरूरत अनुभव होती है। अगर गुंजाइश हो तो इस पर विचार करें। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अपनी इस बात को दोहरता हूं कि यह बजट दिशाहीन बजट नहीं है, स्पष्ट दिशा वाला है। यह ड्रीम बजट नहीं है, चटपटा बजट नहीं है बल्कि व्यावहारिक और प्रेगमेटिक बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री राधाकिशन मालवीयः** (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे ख्याल में मैं आज का अन्तिम वक्ता हूं और कल आप दूसरों को बुलाएंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत प्रस्तुत किया है 1998-99 का, सत्ता पक्ष के लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यह बजट बिल्कुल अर्थहीन बजट है। अमीरों को सहायता देने वाला बजट है और गरीबों को किसी प्रकार की राहत देने वाला यह बजट बिल्कुल नहीं है। बजट बनाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस देश की जनता, इस देश के जरूरतमंद लोग इस देश के गरीब लोगों के ऊपर अधिक से अधिक भार न हो और उनकी आवश्यकता की लगने वाली चीजें उनको सुलभ तरीके से मिल जाएं तथा उन

पर टैक्स की मात्रा कम हो। इस प्रकार का सरकार को बजट प्रस्तुत करना चाहिए। बड़ा विचार करने की बात है कि देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, इन 50 सालों के बाद भी आज तक हम भारत में कोई आर्थिक सुधार वाला बजट नहीं ला पाए हैं। जो गरीब है इस देश में वे और गरीब बनते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वे फायदा लेकर अमीर बनते जा रहे हैं।

मैं इस अवसर पर अपनी 2—4 प्रमुख बातें जो बजट से संबंधित हैं वे रखना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष जी, हमारा देश दुनिया की विशाल जनसंख्या वालों में से दूसरे नम्बर का देश है... (व्यवधान) हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में 7 लाख गांव हैं और देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और उनमें से 70 प्रतिशत जनता खेती का काम करती है, खेती के ऊपर निर्भर है। जब तक हम कृषि को महत्व नहीं देंगे तब तक हमारी आर्थिक नीति असंभव सी लगेगी। खेती की ओर हमको विशेष महत्व देना पड़ेगा और जो भी पिछली सरकारें आई उन्होंने इस देश में हरित क्रांति लाकर आज अनाज के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनाया। मगर अभी पिछली सरकार ने एक जो निर्णय लिया गेहूं आयात करने का, वह उस वक्त लिया जब कि भारत के किसानों के पास गेहूं की फसल अपने खलिहान में आने को तैयार थी। उस वक्त आस्ट्रेलिया से भारत सरकार ने 850 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से 1,000 करोड़ रुपए का गेहूं उन्होंने खरीदा। कुछ समझ नहीं आता है कि अनाज की कमी हमारे यहां थी नहीं और विदेश से इस अनाज की कोई जरूरत थी नहीं मगर जरूरत थी तो 850 रुपए का भाव देना एक शंका की दृष्टि में आता है जबकि हमारे देश में आज हम समर्थन मूल्य में किसानों को 510 रुपए का भाव दे रहे हैं। भारत के लोग जो खेतों में मेहनत करते हैं, रात और दिन इस देश के 70 प्रतिशत लोग जो खेती पर निर्भर हैं, खेतों में काम करते हैं, जो मेहनत करके पूरे देश का पालन-पोषण करते हैं उनको हम समर्थन मूल्य 510 रुपये दे रहे हैं और आस्ट्रेलिया की सरकार को 850 रुपए हमने दिए। इस प्रकार से हमारे देश के किसानों को 340 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने कम दिया ....(व्यवधान) किसी की भी सरकार की बात हो। यह पिछली सरकार की बात की है। कोई हमारी सरकार नहीं थी। तो मेरा सरकार से और विशेषकर वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें जरूर कुछ साजिश है ...(व्यवधान) कोई भी इसमें इन्वाल्व हो।

**प्रो॰ रामलखन सिंह वर्मा:** इसलिए समर्थन वापस लिया।

**श्री राधाकिशन मालवीय:** अब यह तो आप समझें।

इस साजिश की जांच होनी चाहिए कि गेंहूं बाहर से क्यों खरीदा, क्यों महंगे भाव पर लिया? आज हमारे किसानों से क्यों सस्ते दाम पर गेहूं ले रहे हैं? बाहर से महंगे भाव पर क्यों खरीदा? इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। अगर यह जांच नहीं होती है तो हम समझेंगे कि हमारे देश के किसानों के साथ एक कुठाराघात हो रहा है। उपसभाध्यक्ष जी, एक बड़ी विचित्र बात है कि कारखानें में पैदा करने वाला कारखाने का मालिक जो चीज़ वह उत्पन्न करता है उसकी कीमत तो वह स्वयं निर्धारित करता है कि इसकी कीमत इतने-इतने रुपये होगी, मगर भारत का किसान जो रात-दिन मेहनत करता है, जो अनाज पैदा करता है या जो भी उत्पादन करता है, ये कृषि भवन में बैठने वाले लोग उन किसानों के उत्पन्न किए हुए अनाज के मूल्य का निर्धारण करते हैं? ये क्या कभी किसानों के खेत में गए हैं, कभी खेती इन्होंने की है, कभी देखा है कि किसान खेती में कितनी मेहनत करता है? मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब कृषि उपज का कोई मूल्य निर्धारण हो तो उसमें किसान प्रतिनिधि अवश्य रूप से रहे और किसान प्रतिनिधि भी आप एक-तरफा मत रखना। गेहूं के इलाके में गेहूं वाले को, चावल के इलाके में चावल वाले को, जहां पर जो अनाज इस देश में पैदा होती है उस इलाके का किसान प्रतिनिधि उस चीज़ के भाव निर्धारण में होना अति आवश्यक है। जैसा अभी मैंने कहा कि 510 रुपये गेहूं का सरकार समर्थन मूल्य दे रही है। समर्थन मूल्य कृषि आयोग निर्धारित नहीं करता है, इसको वाणिज्य मंत्रालय निर्धारित करता है, व्यापार करने वाला मंत्रालय निर्धारित करता है कि समर्थन मूल्य यह रहेगा। कुछ समझ में नहीं आता है कि वाणिज्य मंत्रालय का काम तो व्यापार करने का है, मूल्य निर्धारण करने का नहीं है, मगर किसानों को जो समर्थन मूल्य देते हैं उसका निर्धारण वाणिज्य मंत्रालय करता है उसकी वजह यह है कि आज इस देश का किसान संगठित नहीं है और संगठित नहीं होने के कारण ही आज किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है और उनके द्वारा उत्पादित चीज़ों के दाम दूसरे लोग निर्धारित करते हैं। जहां तक इस देश की अर्थ व्यवस्था का सवाल है, तो दूसरे धंधे में लगे हुए जो लोग हैं उनकी आमदनी अधिक है और जो खेती के धंधे में लगे लोग हैं उनकी आमदनी अन्य उद्योग-धंधों में लगे हुए लोगों की आमदनी से 6 गुना कम है। इसलिए इसकी ओर विशेष ध्यान दे करके किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। जहां तक सबसिडी का मामला है, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाशियम

(एन०पी०के०) सरकार ने यह बात कही है कि सबसिडी बरकरार रखेंगे। मगर यूरिया पर आपने एक रुपया प्रति किलो, मूल्य बढ़ाया है प्रति क्विंटल या टन का हिसाब नहीं, टन पर अगर डालते तो देश की जनता चिल्ला देती, मगर आपने एक रुपया प्रति किलो बढ़ाया ताकि लोग समझ नहीं पाएं आपने 500 रुपया टन के हिसाब से यूरिया का भाव बढ़ाया और यह कहा है कि किसान यूरिया ज्यादा उपयोग करता है, यह बात सच है कि इस देश का किसान अनपढ़ है, मगर खेती के मामले में वह समझता है कि उसको नाइट्रोजन कितना डालना है, फास्फेट कितना डालना है, पोटाशियम कितना डालना है और कंपोस्ट खाद को कितना डालना है। वह हर चीज़ को जानता है। वह जानता है कि अगर वह यूरिया का अधिक उपयोग करेगा तो उसकी फसल ही नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी।

प्र०प० 10

वह संतुलित मात्रा में यूरिया का उपयोग करता है। तो यह समझ में नहीं आया कि यूरिया के ऊपर पहले एक रुपया बढ़ाया, फिर उस को पचास नया पैसा किया। ...(व्यवधान)...

**श्री नोलोत्पल बसु:** फसल का हिसाब कल ले लेंगे। उर्वरक आज हो गया, कल फसल आ जाएगी।

**उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी):** उन को समाप्त कर ने दीजिए।

**श्री राधाकिशन मालवीय:** उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पेट्रोल के ऊपर भी एक रुपया बढ़ाया गया। जिस दिन पेट्रोल के दाम आप ने बढ़ाए, उस दिन कई लोगों ने 3 से 4 रुपए ज्यादा उस की कीमत वसूल की। फिर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि हम ने सिर्फ एक रुपया प्रति लिटर बढ़ाया है और यह जो एक रुपया प्रति लिटर बढ़ाया है, उस से सरकार को जो 790 करोड़ रुपये इनकम होगी, वह हम अपने राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च करेंगे। मगर मेरा सरकार से कहना है कि किधर का फंड किधर खर्च करेंगे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मूल्य वृद्धि यदि आप वापिस कम कर दें तो बहुत अच्छा होगा।

आप किसान के लिए क्रेडिट कार्ड देने का एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, मगर इस में भी एक विडम्बना है कि किसान का मतलब तो किसान ही होता है—एक सौ एकड़ वाला हो, पचास एकड़ वाला हो या एक एकड़ वाला हो, वह किसान ही होता है। तो इस योजना में उस का कैसे समावेश होगा ताकि उस को अपनी क्रेडिट के आधार पर खाद, बीज, दवाई उपलब्ध हो जाए। इस के लिए आप को इस योजना में पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप ने बंजर भूमि के ऊपर भी 150 करोड़ रुपये गए साल के बजट से ज्यादा वृद्धि इस में की है। मेरा सरकार से कहना है कि मध्यप्रदेश में बंजर भूमि, ऊसर भूमि और चंबल के बीहड़ की लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। यदि आप इस में धनराशि और बढ़ाएं और इस जमीन को खेती के उपयुक्त बनाएं तो इस से हमारे देश के लोगों को ज्यादा अनाज मिलेगा। आज इस देश में 80 मिलियन हैक्टेयर भूमि पड़ती पड़ी हुई है और हमारे मध्य प्रदेश में तो तरह की भूमि बहुत ज्यादा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश का किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मरता है। जब वह कोऑपरेटिव बैंक या कॉमर्सियल बैंक से कर्ज लेता है और प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि वगैरा आ जाती है, तो वह ब्याज और ब्याज के ऊपर दंड ब्याज व कई तरह की पेनल्टी से और दब जाता है और कर्ज जमा नहीं कर पाता है। इस कारण वह कुछ कर लेता है, जैसे कि पिछले दिनों कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के किसानों ने आत्म-हत्या कर ली। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर किसी किसान ने कर्ज लिया है तो आप उस से मूलधन का दोगुना वसूल कर के उसे कर्ज से मुक्त कर दीजिए। उस से ब्याज पर ब्याज चढ़ाकर मूलधन से कई गुना अगर वसूल करेंगे तो किसान कभी भी कर्ज से उभर नहीं पाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मूलधन से दोगुना लेकर उस को कर्ज से मुक्त किया जाए।

उपसभाध्यक्ष जी, अब मैं पीने के पानी पर आता हूं। सरकार ने पीने के पानी के ऊपर इस साल के बजट में 1627 करोड़ रुपये रखें हैं और आप ने कहा है कि हम एक लाख बस्तियों को लाभांवित करेंगे। महोदय, यह इतना बड़ा देश है जोकि आज एक सौ करोड़ की आबादी पर पहुंच रहा है और आप कह रहे हैं कि हम एक लाख बस्तियों लाभांवित करेंगे। फिर उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में पानी 12 रुपये से 14 रुपये लिटर बिक रहा है। हम देश के गरीबों को पानी भी नहीं पिला सकते हैं। हमारे यहां दूध भी दस रुपये लिटर बिक रहा है। आपने पेट्रोल का भाव बढ़ाया, मगर डीजल का भाव 10/- रुपये लिटर रहा है और पानी 14/- रुपये, 15/- रुपये लिटर बिक रहा है, मिनरल वाटर। मेहरबानी करके सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज गांवों में पीने का पानी नहीं है। गरमी के सीजन में उनके ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं, तालाब का पानी सूख गया है।

वाटर लेवल जमीन के काफी नीचे गहरे में 400 फीट, 500 फीट पर चला गया है। इस पर विचार जरूरी है कि हम किस प्रकार से जल संग्रहण करके उस वाटर लेवल को ऊपर बढ़ाएं और सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में पीने की पानी की व्यवस्था करानी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, यहां दिल्ली की हालत यह है कि मैं कैनिंग लेन में रहता हूं, नल में पानी नहीं आता, टैंकर बुलाना पड़ता है। रोज पीने के पानी के लिए एक मैम्बर पार्लियामेंट की टेलीफोन करके पानी का टैंकर मंगाना पड़े तो वह लोग भी कहते हैं कि यह अच्छे मैम्बर पार्लियामेंट है, क्या करते हैं पानी का, क्या पानी-पानी डोलते रहते हैं। दिल्ली जैसे शहर में पाने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, रोज समाचार पत्रों में आता है पीने के पानी का। जबकि यमुना नदी यहां है, उसको तो इन्होंने प्रदूषण से खराब कर दिया। मेहरबानी करके इस देश के बड़े शहरों के साथ हमारे जो छोटे शहर, हमारे जो गांव हैं वहां भी पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान दीजिए।

मान्यवर, एक मिनट में खत्म कर दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि की है, मगर इस देश की जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें आज जो बड़े घर का संपन्न व्यक्ति है वह तो अपने बच्चों को कान्वेन्ट स्कूल में, पब्लिक में, किसी बड़े स्कूल में, जहां अच्छी शिक्षा मिलती है वहां पढ़ाता है और जो इस देश का गरीब आदमी है वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। उसके बाद जब नौकरी की बात आती है तो कंपीटीशन के मामले से गरीब के बच्चे को कभी नौकरी नहीं मिलती है। अगर वह नौकरी मिलेगी तो बड़े घर के बच्चे को, जो बड़े स्कूल में पढ़ा है, मैरिट के आधार पर आगे आ जाता है। क्या सरकार इस बात पर विचार नहीं कर सकती कि हम इस देश में समान शिक्षा ला सकें? आप आज की शिक्षा से बड़े को और बड़ा बना रहे हैं और गरीब को और जमीन में दबा रहे है। इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस देश में जो 30 करोड़ गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी हम शिक्षा तो कम से कम समानता की दें। इस देश का कैसे उद्धार होगा, यदि हम शिक्षा के मामले में समानता न बरत कर भेदभाव की नीति से शिक्षा देंगे?

मान्यवर, आवास के मामले में 1600 करोड़ रुपयें रखे गए हैं। आज हम देखते हैं, मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, और दूसरे बड़े-बड़े शहरों में, कि हजारों लोग फुटपाथ पर सोते हैं। जब विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं, रेलवे स्टेशन पर देखते हैं लोगों को भीख मांगते हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जिनके पास रहने को मकान भी नहीं होता, तो हमारे सामने भी यह एक सोचनीय प्रश्न हो जाता है, विचारणीय प्रश्न हो जाता है। क्या हम इस देश के लोगों के रहने के लिए मकान नहीं बना सकते? मकानों के लिए आपने बजट में व्यवस्था की है, मगर बहुत कम की है। इसका सर्वे कराया जाना चाहिए पूरे देश में, कि जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए हम अनिवार्य रूप से कैसे मकान बनाएंगे? आप किसी भी चीज में कटौती कर दीजिए इस देश के हर निवासी के रहने के लिए मकान, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज की व्यवस्था हो। अगर ऐसा होता है तो यह देश संपन्नता की ओर आगे बढ़ सकता है।

मान्यवर, आज देश में 12 करोड़ लोग बेकार, बेरोजगार है। अभी दिल्ली में कल हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने जब इसको लेकर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठियों से उनको मारा और घायल किया। अरे, वह तो मांग कर रहे थे। आपने राष्ट्रीय सेवा में 58 साल से 60 साल की उम्र कर दी है। इससे जो नौकरी में है, वे तो खुश हैं कि हमारी 60 साल उम्र तक की नौकरी हो गई, दो साल हमको और आटोमैटिक एक्सटेंशन मिल गया, मगर आपने इस बात पर भी विचार किया कि इस देश के जो बेरोजगार लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, जिनको नौकरी की आवश्यकता है, वे तो दो साल और पीछे चले गए। जिनको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, उनको हम और पीछे धकेल रहे।

तो माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इन बातों पर आज विशेष ध्यान देंगे और मैंने जो कुछ बातें रखी हैं, उनकी ओर आप विशेष ध्यान देंगे और जो आपने महंगा बजट बनाया है, जो 1800 सीसी के ट्रैक्टर पर 8 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया है, वह कम करेंगे। आपने चाय महंगी कर दी है, डिब्बाबंद चाय, सभी पीते हैं, उस पर भी आपने 8 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। ब्रांडिड मक्खन, क्रीम पर भी आपने शुल्क लगा दिया है। तो इस प्रकार जिन चीजों के आपने शुल्क बढ़ाए है, उनको कम करेंगे तो अच्छी बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at ten minutes past ten of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 10th June, 1998.